सत्यमेव जयते

राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड
प्रेस विज्ञप्ति–2

• राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी

- **गणतन्त्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य रविवार 26 जनवरी को प्रातः 8:30 बजे राजभवन प्रांगण में तथा 10:30 बजे परेड ग्राउण्ड में ध्वजारोहण करेंगी।**
- **राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य के निर्देशों के क्रम में 26 जनवरी, 2020 को प्रातः 10:00 बजे से 2:00 बजे तक राजभवन परिसर आमजन के लिए खुला रहेगा।**

राजभवन देहरादून 25जनवरी, 2020

राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश वासियों को गणतन्त्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने कहा है कि '' यह वर्ष उत्तराखण्ड के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष हम अपनी स्थापना के 20 वर्ष भी पूर्ण करेंगे। राज्य के समग्र विकास के लिये ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएँ पर्याप्त रूप से प्रदान करने की आवश्यकता है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक नीतिगत सुधार भी किये जा रहे हैं।''

राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने कहा है कि महिलाएँ इस प्रदेश के विकास की धुरी हैं। महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा कर प्रदेश के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें महिलाओं के साथ–साथ उनके छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की चिन्ता भी करनी होगी। राज्य में गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों के पोषण में सुधार लाने के लिये पोषण अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बेटियों को माँ के गर्भ से ही सुरक्षित वातावरण देना हम सबकी जिम्मेदारी है। कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है। आज बेटियों ने सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिलें तो वे किसी से कम नहीं हैं। महिलाओं को घर में तथा कार्य स्थल पर पूरी समानता, सम्मान और सुरक्षा मिलनी ही चाहिये। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। होम स्टे योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि से जोड़ा जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक देश में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखण्ड राज्य में भी इस हेतु ''मिट्टी से बाजार तक'' की नीति लागू की गई है। किसान भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि वे जैविक कृषि की दिशा में आगे आयें और उत्तराखण्ड को एक पूर्ण जैविक राज्य बनाने में अपना योगदान दें।

उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूली व उच्च शिक्षा की क्वालिटी में और अधिक सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक–एक गांव गोद लेकर इसे पूर्ण रूप से मॉडल स्मार्ट विलेज बनाने का निर्देश भी दिया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में उत्तराखण्ड जल नीति 2019 भी लागू कर दी गई है। भारत में जल संकट को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक जल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 'जल जीवन मिशन' की घोषणा की है। हम सभी को इस महान संकल्प की सिद्धि के लिए अपना शत प्रतिशत योगदान देना होगा।

---0----